

अमृत कलश टाइम्स



वर्ष : 18
अंक : 101

प्रयागराज शुक्रवार 27 दिसम्बर 2024

पृष्ठ- 4, मूल्यः- एक रुपया

यूपीः विद्या स्कूलों में फिर शुरू होंगी नाग पंचमी

● अनंत चतुर्दशी और पितृ विसर्जन की छुट्टियां, सीएम को लिखा पत्र

लखनऊ,(एजेंसी)। यूपी के स्कूलों में नाग पंचमी, अनंत चतुर्दशी, पितृ विसर्जन, नवरात्रि पहले दिन की छुट्टी फिर से शुरू करने की मांग की गई है। इस बारे में शिक्षक संगठन ने सीएम को पत्र लिखा है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर परिषदीय विद्यालयों में भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रमुख पर्याप्त की छुट्टियां फिर से बहाल करने की मांग की है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विद्यालयों की सिंह नामक विद्यालय ने विद्यालयों ने पर्याप्त की महत्व जाने बिना ही पूर्व में कई पर्याप्त की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। इसके कारण



विशेषी बन रही है। मौनी अमावस्या, भैयादूज, जमात उल विदा (अलविदा), नाग पंचमी, अनंत चतुर्दशी, पितृ विसर्जन, नवरात्रि पहले दिन की छुट्टी पूर्व में होती थी। किंतु अधिकारियों ने बिना इन पर्याप्त की महत्व जाने इनको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके कारण शिक्षक व बच्चे अपने पारिषदीय

सामाजिक एवं धार्मिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस तथ्य की जांच की मांग की है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विद्यालयों को इनकी छुट्टी समाप्त किया गया। उन्होंने बच्चों से कहा कि इसका कारण विद्यालयों की समाप्त किया गया। अद्वृत उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके पास असाधारण विद्यालयों की सुविधा के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। बमरीली वायुसेना स्टेशन पर इन्स्ऱूल्मेट लैंडिंग सिस्टम को कैट-प्राइम एलेवेलर के साथ संचालन को सुविधाजनक बनाया जा सके। स्टेशन ने कोशिकी से एयरपोर्ट हाईवे और बंगल बाजार में रेलवे ओवर ब्रिज (आरओई) के चार लेन के निर्माण और तीजी से खोलने की सुविधा प्रदान की है तथा सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल के समय पर विस्तार के लिए भारतीय विमानपत्रन प्राधिकरण (एएआई) को हर संभव सहायता प्रदान की गई है। भारतीय वायुसेना ने मेना स्थल पर एक समर्पित बचाव समन्वय दल बनाए रखने की भी योजना बनाई है।

महाकुंभः सहायता और आपदा राहत में अहम भूमिका निभाएगा

प्रयागराज। आगामी महाकुंभ में मध्यवायु कमान नागरिक उड्डयन गतिविधि को बढ़ावा देने से लेकर मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) कवर के प्रावधान तक महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा। वायुसेना स्टेशन बमरीली 20 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक 24x7 आधार पर सिविल अनुसूचित और चार्टर्ड उड़ान के लिए महाकुंभ - 2025 के लिए उड़ान संचालन की सुविधा के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। बमरीली वायुसेना स्टेशन पर इन्स्ऱूल्मेट लैंडिंग सिस्टम को कैट-प्राइम एलेवेलर के साथ संचालन को सुविधाजनक बनाया जा सके। स्टेशन ने कोशिकी से एयरपोर्ट हाईवे और बंगल बाजार में रेलवे ओवर ब्रिज (आरओई) के चार लेन के निर्माण और तीजी से खोलने की सुविधा प्रदान की है तथा सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल के समय पर विस्तार के लिए भारतीय विमानपत्रन प्राधिकरण (एएआई) को हर संभव सहायता प्रदान की गई है। भारतीय वायुसेना ने मेना स्थल पर एक समर्पित बचाव समन्वय दल बनाए रखने की भी योजना बनाई है।

बिहार सरकार निरंकुश हो चुकी है: पप्पू यादव

पटना,(एजेंसी)। बिहार में पूर्णीया के सासद पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की सरकार निरंकुश हो गयी है। श्री यादव बुधवार की देर रात गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे और उन्होंने बिहार लोक सेना आयोग (बीपीएससी) परीक्षार्थियों से बातचीत की। उन्होंने धरना स्थल पर लाठीचार्ज से घायल छात्रों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार निरंकुश हो चुकी है। छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना निंदनीय है। निहथे छात्रों पर लाठी चलाने की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगा। सासद ने कहा कि सरकार चाहे जितना भी जुल्म छात्रों पर कर ले उसे बीपीएससी की फिर से परीक्षा लीनी होगी। मैं छात्रों के साथ रह कदम पर खड़ा हूँ। छात्रों की लड़ाई में सड़क से लेकर सदन तक लड़ूँगा। उन्होंने छात्रों से आवाहन करते हुए कहा की आप अपनी आंदोलन की ताकत को बढ़ाइए हमारा पूरा सपोर्ट इस आंदोलन को रहेगा।

पटना,(एजेंसी)। बिहार में पूर्णीया के सासद पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को बाहर करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) का कहना है कि कांग्रेस भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं में भरी नाराजगी है। आप सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने के लिए आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से बातचीत करेगी। आप का कहना है कि कांग्रेस भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की मांग व कांग्रेस के नेताओं के बयानों को लेकर आम आदमी पार्टी 24 घंटे में अजय मानक पर हो कार्रवाई आप अप नेता संजय सिंह ने कहा कि आप के विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से कथित तौर पर व्यक्तिगत डेटा मतदाता पहचान पत्र और फोन नंबर एकत्रित किया जा रहा है। आप प्रक्रिया में ऑटोपी सत्यापन का उपयोग किया जा रहा है। जिससे जनता का विश्वास तोड़ा गया है। वहीं दिल्ली सरकार के महिल एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई लोकान्वयन एवं विद्यालय की प्रदेशीय कानूनों की विवादित कानूनों के बारे में शिक्षायत की गई है। लोकान्वयन के बारे में शिक्षायत की है। अक्षय लाकड़ा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर दिल्ली की जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि आप के विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से कथित तौर पर व्यक्तिगत डेटा मतदाता पहचान पत्र और फोन नंबर एकत्रित किया जा रहा है। आप नेता संजय सिंह ने यहां मुख्यमंत्री अतिशी के साथ एक संवाददाता सम्मलेन में कहा, "कांग्रेस नेता अजय मानक भाजपा द्वारा भेजी गयी स्ट्रिक्ट पढ़ते हुए उनका कानून भाजपा के विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से कथित तौर पर व्यक्तिगत डेटा मतदाता पहचान पत्र और फोन नंबर एकत्रित किया जा रहा है।" अप नेता संजय सिंह ने यहां मुख्यमंत्री अतिशी के साथ एक संवाददाता सम्मलेन में कहा, "कांग्रेस नेता अजय मानक भाजपा द्वारा भेजी गयी स्ट्रिक्ट पढ़ते हुए उनका कानून भाजपा के विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से कथित तौर पर व्यक्तिगत डेटा मतदाता पहचान पत्र और फोन नंबर एकत्रित किया जा रहा है।" अप नेता संजय सिंह ने यहां मुख्यमंत्री अतिशी के साथ एक संवाददाता सम्मलेन में कहा, "कांग्रेस नेता अजय मानक भाजपा द्वारा भेजी गयी स्ट्रिक्ट पढ़ते हुए उनका कानून भाजपा के विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से कथित तौर पर व्यक्तिगत डेटा मतदाता पहचान पत्र और फोन नंबर एकत्रित किया जा रहा है।" अप नेता संजय सिंह ने यहां मुख्यमंत्री अतिशी के साथ एक संवाददाता सम्मलेन में कहा, "कांग्रेस नेता अजय मानक भाजपा द्वारा भेजी गयी स्ट्रिक्ट पढ़ते हुए उनका कानून भाजपा के विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से कथित तौर पर व्यक्तिगत डेटा मतदाता पहचान पत्र और फोन नंबर एकत्रित किया जा रहा है।" अप नेता संजय सिंह ने यहां मुख्यमंत्री अतिशी के साथ एक संवाददाता सम्मलेन में कहा, "कांग्रेस नेता अजय मानक भाजपा द्वारा भेजी गयी स्ट्रिक्ट पढ़ते हुए उनका कानून भाजपा के विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से कथित तौर पर व्यक्तिगत डेटा मतदाता पहचान पत्र और फोन नंबर एकत्रित किया जा रहा है।" अप नेता संजय सिंह ने यहां मुख्यमंत्री अतिशी के साथ एक संवाददाता सम्मलेन में कहा, "कांग्रेस नेता अजय मानक भाजपा द्वारा भेजी गयी स्ट्रिक्ट पढ़ते हुए उनका कानून भाजपा के विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से कथित तौर पर व्यक्तिगत डेटा मतदाता पहचान पत्र और फोन नंबर एकत्रित किया जा रहा है।" अप नेता संजय सिंह ने यहां मुख्यमंत्री अतिशी के साथ एक संवाददाता सम्मलेन में कहा, "कांग्रेस नेता अजय मानक भाजपा द्वारा भेजी गयी स्ट्रिक्ट पढ़ते हुए उनका कानून भाजपा के विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से कथित तौर पर व्यक्तिगत डेटा मतदाता पहचान पत्र और फोन नंबर एकत्रित किया जा रहा है।" अप नेता संजय सिंह ने यहां मुख्यमंत्री अतिशी के साथ एक संवाददाता सम्मलेन में कहा, "कांग्रेस नेता अजय मानक भाजपा द्वारा भेजी गयी स्ट्रिक्ट पढ़ते हुए उनका कानून भाजपा के विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से कथित तौर पर व्यक्तिगत डेटा मतदाता पहचान पत्र और फोन नंबर एकत्रित किया जा रहा है।" अप नेता संजय सिंह ने यहां मुख्यमंत्री अतिशी के साथ एक संवाददाता सम्मलेन में कहा, "कांग्रेस नेता अजय मानक भाजपा द्वारा भेजी गयी स्ट्रिक्ट पढ़ते हुए उनका कानून भाजपा के विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से विधायक और एमसीडी पर्यादोन की ओर से कथित तौर पर व्यक्तिगत डेटा मतदाता पहचान पत्र और फोन नंबर एकत्रित किया जा रहा है।" अप नेता संजय सिंह ने यहां मुख्यमंत्री अतिशी के साथ एक संवाददाता सम्मलेन में कहा, "कांग्रेस नेता अजय मानक भाजपा द्वारा भेजी गयी स

दिन होंगे मुश्किल

केंद्रीय भूजल बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट ने देश में भूजल के स्तर को लेकर कुछ ऐसे तथ्य रखांकित किए हैं, जो चिंता पैदा करते हैं। यह चिंता तो पर्यावरणिवादों को लंबे समय से सता रही है कि देश में भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है, लेकिन इस नवीनतम रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल में जहां कुओं के जल स्तर में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है, वहीं राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में कुओं के जलस्तर में आमतौर पर गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में तो 66 फीसदी कुओं में जलस्तर गिरा है। यह स्थिति इसलिए चिंतित करती है कि क्योंकि इस वर्ष देश में अच्छी वर्षा हुई है। राजस्थान में तो भूजल संरक्षण की एक पुष्ट परंपरा है। पश्चिमी राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्टानी है और रेगिस्टान में जल की उपलब्धि कम होने के कारण पारंपरिक तौर पर यहां पानी बचाना सामाजिक जिम्मेदारी का काम माना जाता है। चूंकि रेगिस्टान में जल की उपलब्धि अपेक्षाकृत विरल होती है, इसलिए प्राचीनकाल में तालाब, कुएं, बावड़ी, कुंड या जोहड़ बनवाना बहुत पुण्य का काम माना जाता था।

पश्चिमी राजस्थान के तो कुओं के बास्तु का अध्ययन भी बहुत रोचक हो सकता है। ये कुएं न केवल इन्हें गहरे हैं कि इन्हें पातालतोड़ कुओं कह दिया जाता है बल्कि ये इन्हें विशाल भी होते हैं कि इनके ऊपर हुए निर्माण में बरसों तक सरकारी ऑफिस तक चले हैं। पश्चिमी भारत में कुछ बावडियां तो इन्हीं विशाल हैं कि जरूरत पड़ने पर पूरी सेना इन बावडियों में शरण ले सकती थीं। बूंदी जिले में हिंडोली के तालाब के बारे में एक रोचक कथा है। कहते हैं कि सदियों पहले एक बंजारे ने इधर से गुजरते हुए अपनी बेटी का विवाह यहां के एक युवक से कर दिया। एक दिन बेटी किसी कारण से जब गंदे पांव लेकर घर में घुस गई तो सासू मां ने ताना दिया – ‘तेरे पिता ने कौनसा तालाब बनवा रखा है, जो बार–बार घर साक करने के लिए यहां पानी बहाते रहेंगे?’ यह बात बंजारे को पता चली तो वह अपने काफिले के साथ आया और उसने गांव में सचमुच तालाब बनवा दिया। प्राचीनकाल में श्रेष्ठियों के घरों में, मदिरों में, सामुदायिक भवनों में और सार्वजनिक स्थलों पर कुएं हुआ करते थे। उस दौर में कुएं, बावड़ी, कुंड, तालाब, जोहड़ वर्षा जल को स्वयं में संचित करके न केवल आसपास की आबादी को रोजमर्झ की आवश्यकता के लिए जल उपलब्ध कराते थे, बल्कि भूजल स्तर को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका आदा करते थे।

समय और सामाजिक काल के बदलती हुई प्राथमिकताओं ने अधिकांश प्राचीन कुओं, बावडियों, तालाबों, कुंडों को उपेक्षा के गर्त में धकेल दिया। दुर्भाग्य से नदियां तो प्रदूषण की मार झेल ही रही हैं, बरसात के पानी के संरक्षण को लेकर भी सामाज बहुत सजग नहीं रह गया है। 70 के दशक के अंत में जब गांव–गांव में नलकूपों के माध्यम से जलापूर्ति संभव करने का अभियान चला तो धरती की गोद में छुपे पानी के भंडारण को अपनी आवश्यकता के अनुसार बाहर निकालने का साधन तो लोगों को मिल गया लेकिन धरती के अंक की जल समृद्धि को बचाए और बनाए रखा जा सके, इस दृष्टि से गंभीर प्रयास नहीं हुए। कुछ लोगों को लगता है कि पृथ्वी की दो तिहाई सतह पानी से ढंकी हुई है, फिर पानी की कमी की सम्भावना को लेकर इन्हीं हाय—तौबा क्यों? दरअसल, उन लोगों को यह नहीं मालूम कि दुनिया में उपलब्ध कुल पानी का केवल दो से तीन प्रतिशत पानी ही शुद्ध रूप में मनुष्य उपयोग कर सकता है और अभी दुनिया में आबादी का एक बड़ा हिस्सा पानी की कमी का सामना कर रहा है। भारत जैसे देश में, जहां अधिकांश इस्सों में नदियों का जाल है, दुनिया की आबादी का 17 प्रतिशत द्विसारा रहता है, पानी की उपलब्ध मात्रा दुनिया के कुल स्वच्छ जल का केवल चार प्रतिशत है। पानी की बचाना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। केवल जिम्मेदार संस्थानों के प्रवाधनों से स्थिति में सुधार नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज को समझना होगा कि यदि भूजल का संरक्षण नहीं किया गया, भूजल का दुरुपयोग बंद नहीं किया गया तो पीढ़ियों के लिए दिन बहुत मुश्किल भरे होंगे।

कटाई पर हर हाल में अंकुश जरूरी

ऐसे दौर में, जब पर्यावरण विशेषज्ञ दुनियास्पद में घटने जंगलों पर चिंता जता रहे हैं, भारतीय वन संरक्षण (एफएसआइ) की मार रहती है। इसके मुताबिक 2021 से 2023 तक भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। देश को हरा-भरा रखने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी दो साल पहले के मुकाबले हरायाती बढ़ी है। इससे संकेत मिलते हैं कि देश में कई सालों जारी रहने वाली दिनांक है कि उत्तराखण्ड और असाम के साथ इन राज्यों में वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र घटा है। इसके कारणों की समीक्षा के साथ इन राज्यों में वनों के संरक्षण और सर्वर्धन पर ध्यान देने की जरूरत है।

राष्ट्रीय स्तर पर वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र का दायरा बढ़ने के बावजूद परिवर्षिक सुरक्षा की दृष्टि से लक्ष्य फिलहाल काफी दूर है। देश की वन नीति को देखा से कुल भौगोलिक क्षेत्र में 33 फीसदी हिस्सेदारी वन क्षेत्र की जोहड़ी रही है। एफएसआइ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यह हिस्सेदारी 2017 में 17 फीसदी तक ही पहुंची है। एफएसआइ ने सर्वेक्षण रिपोर्ट की शुरुआत 1987 में की थी। तब से अब तक यह हिस्सेदारी कीरीब दो फीसदी ही बढ़ी है। हर दो साल में जारी होने वाली रिपोर्ट में वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में घट-घट होती रहती है। कुल भूमि के मुकाबले वनों के अनुपात का ग्राफ ज्यादा ऊपर नहीं उठता। जाहिर है, दुनिया के दूसरे देशों की तरह जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण भारत में भी जंगल राष्ट्रिक तौर पर फल-फूल नहीं पार रहे हैं। ये रिपोर्ट एवं वनों के संरक्षण और सर्वर्धन पर ध्यान देने की चिंता जाता रहा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कटाई से हर साल करीब एक करोड़ हेक्टेएक्ट वन क्षेत्र घट रहा है। दो साल पहले एक रिपोर्ट के वन क्षेत्र में 22,62 वर्ग किलोमीटर की कमी आई। यानी जहां बाध रहते हैं, वहां भी जंगल सिक्कूर रहे हैं। पूर्वोत्तर में हाइवे और एयरपोर्ट बनाने की भरपाई से वृक्षरोपण से नहीं की जाती कमी। ऐसा इसलिए व्यांकिंग कंजंगल कटाई के लिए वैशिक्ष

कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना जरूरी

समीर पंडित

भारत का लक्ष्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना है, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईटी) परिवहन क्षेत्र को कार्बन-मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हालांकि, ईटी को व्यापक रूप से अपनाना एक विश्वसनीय और सुलभ वार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहन वार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संचालन के लिए दिशा-निर्देश 2024 जारी किए हैं। यह देश भर में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में तेजी लाने के लिए डिजिटल किया गया एक दांव है। एक मजबूत वार्जिंग नेटवर्क का निर्माण न केवल सुविधा के लिए बल्कि ऊर्जा, सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ उठाने और वार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए विशेषताएं।

दिशा-निर्देश 2024 शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों एवं दोपहिया वाहनों से लेकर भारी-भरकम ट्रकों तक, विभिन्न प्रकार के वाहनों की जरूरतों को पूरा करने वाले वार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज गति से विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करते हैं। दिशा-निर्देश 2024 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

सार्वजनिक और निजी वार्जिंग स्टेशनरूल दिशा-निर्देश 2024 में जारी होने वाले भारी-भरकम ट्रकों तक, विभिन्न प्रकार के वाहनों की जरूरतों को पूरा करने वाले वार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज गति से विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करते हैं। दिशा-निर्देश 2024 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

सार्वजनिक और निजी वार्जिंग स्टेशनरूल दिशा-निर्देश 2024 में जारी होने वाले भारी-भरकम ट्रकों तक, विभिन्न प्रकार के वाहनों की जरूरतों को पूरा करने वाले वार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज गति से विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करते हैं। दिशा-निर्देश 2024 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

पारंपरिक और निजी वार्जिंग स्टेशनरूल दिशा-निर्देश 2024 में जारी होने वाले भारी-भरकम ट्रकों तक, विभिन्न प्रकार के वाहनों की जरूरतों को पूरा करने वाले वार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज गति से विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करते हैं। दिशा-निर्देश 2024 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं। एक डिस्कॉर्म के रूप में, आप अपने ग्रिड को स्थिर करने में मदद करने के लिए स्मार्ट ईटी वार्जिंग को प्राप्ति करता है। ईटी को सिस्टम में आसानी से एकीकृत करने की अनुमति देंगे, क्योंकि अप्रबंधित वार्जिंग आपके ग्रिड को ओवरलोड कर आपके परिवालन व्यय को बढ़ा सकती है। वार्जिंग स्टेशन पर अपने वाहनों की सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं। एक डिस्कॉर्म के रूप में, आप अपने ग्रिड को स्थिर करने में मदद करने के

